

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राजशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 29 मार्च, 1986/8 चैत्र, 1908

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचनायें

शिमला-2, 22 फरवरी, 1986

गृह (ए)-7(जी)-19/75-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल मैजोर फील्ड कार्यालय एवं आर्टिलरी प्रैक्टिस अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवां अधिनियम) की धारा 9 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) में अपेक्षित है इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अधीन उस क्षेत्र में जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार गृह विभाग की अधिसूचना संख्या गृह- (ए)-7 (जी) -19/75, दिनांक 7-8-1981 तथा 24-9-1981 जो कि असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश के 29

अगस्त, 1981 के अंक में प्रकाशित हुई थी, में विनिर्दिष्ट किये गए हैं में निम्नलिखित अवधि के दौरान पूर्व परिभाषित क्षेत्रों में फील्ड फायरिंग तथा आर्टिलरी प्रैक्टिस करने हेतु प्राधिकृत करने के निश्चय को सरकारी राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना उन लोगों की सूचना हेतु, जो कि उसक द्वारा प्रभावित होने सम्भव हैं सहर्ष प्रकाशित करते हैं :—

अगस्त 1986

1 से 2 तक
4 से 5 तक
7 अगस्त 1986
9 अगस्त 1986
11 से 12 तक
14 अगस्त 1986
16 अगस्त 1986
18 से 19 तक
21 से 23 तक
25 से 26 तक
28 से 30 तक

सितम्बर 1986

1 से 2 तक
4 से 6 तक
8 से 9 तक
11 से 13 तक
15 से 16 तक
18 से 20 तक
22 सितम्बर 1986
25 से 27 तक
29 से 30 तक

दिसम्बर 1986

16 दिसम्बर 1986
18 से 20 तक
22 से 23 तक

जनवरी 1987

1 से 3 तक
5 से 6 तक
8 से 10 तक
12 से 13 तक
15 से 17 तक
19 से 20 तक
22 से 24 तक
27 जनवरी 1987
29 से 31 तक

फरवरी 1987

2 से 3 तक
5 से 7 तक
9 से 10 तक
12 से 14 तक
16 से 17 तक
19 से 21 तक
23 से 24 तक

ए० के० मोहापात्र,
सचिव ।

Shimla-171002, the 26th February, 1986

No. HOM (A)-A (9)-37/80-IV.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Security Act, 1980 (Act 65 of 1980), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to specify by general order that any person detained under section 3 of the said Act by the Government or by the District Magistrate authorised in this behalf shall be detained in a Police lock up or kept in any jail in Himachal Pradesh, subject to the conditions as to maintenance/discipline and punishment for breaches of discipline specified in the Himachal Pradesh Detenus (Conditions of Detention) Order, 1980.

Shimla-171002, the 26/27th February, 1986

No. HOM (A)-A (9)-37/80-IV.—In exercise of the powers vested in him under para-II of sub-section (3) of section 3 of the National Security Act, 1980 (Act No. 65 of 1980), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to authorise District Magistrates in Himachal Pradesh, within their respective jurisdiction to exercise the powers of the State Government under sub-section (2) of section 3 of the aforesaid Act delegated *vide* this Government Notification of even number, dated the 27th May, 7th October and 30th November, 1985 for another three months *i.e.* upto 25th May, 1986.

By order,
A. K. MOHAPATRA,
Secretary.

सामान्य प्रशासन विभाग
(मन्त्रिमण्डल एवं संमदीय कार्य विभाग)

अधिसूचना

शिमला-2, 20 फरवरी, 1986

संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी)-49/78-सी-IV.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सैलरीज एण्ड ग्राजु सिज आफ मिनिस्टर (हिमाचल प्रदेश) ऐक्ट, 1971 (1971 का 3) की धारा 7-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण), तारीख 31 मार्च, 1981 में अधिसूचना संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी)-49/78-सी भाग-II, तारीख 30-3-81 द्वारा प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश मन्त्री (भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण) नियम, 1981 में संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मन्त्री (भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण) नियम, 1986 है।
(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मन्त्री (भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण) नियम, 1981 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “कथित नियम” कहा गया है) नियम 4 में शब्द “साठ” के लिए “एक लाख और बीस” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और कथित नियमों के नियम 4 के अन्त में चिह्न “.” के लिए “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक “क” जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु, यदि मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर (एड्वांस फार मोटर कार) ऐक्ट, 1971 के नियम 4 के अधीन मन्त्री द्वारा पहले मोटर कार के लिए लिये गए अग्रिम ऋण सहित, भवन निर्माण अग्रिम ऋण की कुल राशि एक लाख बीस हजार रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी।”

[Authoritative English text of the notification No. GAD (PA)-4(D)-49/78-C-IV, dated 20-2-1986 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, is hereby published for general information].

Shimla-2, the 20th February, 1986

No. GAD (PA)-4(D)-49/78-C. IV.—In exercise of the powers conferred by section 7-A of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 3 of 1971), the

Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981, published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra-ordinary), dated the 31st March, 1981 vide notification No. GAD(PA)-4(D)-49/78-C-Vol.II, dated 30-3-1981, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Ministers (Advance of Loan for House Building) (Amendment) Rules, 1986.

(2) These rules shall come into force at once.

2. **Amendment of rule 4.**—For the word “sixty” occurring in rule 4 of the Himachal Pradesh Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981 (hereinafter called the “said rules”), the words “one lakh and twenty” shall be substituted and for the sign “.” occurring at the end of rule 4 of the said rules, the sign “:” shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that in case a Minister has taken the motor car advance under rule 4 of the Himachal Pradesh Minister (Advance for Motor Car) Rules, 1971 the total amount of the house building advance together with the motor car advance already availed of by a Minister, shall not exceed the limit of one lakh and twenty thousand rupees.”.

शिमला-171002, 20 फरवरी, 1986

संख्या जी 0 ए 0 डी 0 (पी 0 ए 0)-4(डी)-49/78-सी-IV.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सैनरीज एण्ड अलाउंसिज आफ डिप्टी मिनिस्टर (हिमाचल प्रदेश) ऐक्ट, 1971 (1971 का 5) की धारा 8-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण), तारीख 26-3-83 में, अधिसूचना संख्या जी 0 ए 0 डी 0 (पी 0 ए 0)-4 (डी) 46/82, तारीख 22-2-1983 द्वारा प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश उप-मन्त्री (भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण) नियम, 1982 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उप-मन्त्री (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1986 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश उप-मन्त्री (भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण) नियम, 1982 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “कथित नियम” कहा गया है) के नियम 4 में शब्द “साठ” के लिए “एक लाख और बीस” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और कथित नियमों के नियम 4 के अन्त में चिह्न “.” के लिए “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसमें पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक “क” जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यदि उप-मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश डिप्टी मिनिस्टर (एडवान्स फार मोटर कार) एक्ट, 1971 के नियम 4 के अधीन मोटर कार के लिए उप-मन्त्री द्वारा अग्रिम ऋण लिया हो तो लिए गए पहले मोटर कार के लिए अग्रिम ऋण सहित, भवन निर्माण अग्रिम ऋण की कुल राशि, एक लाख बीस हजार रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी।”

[Authoritative English text of the notification No. GAD(PA)-4(D)-49/78-C.IV, dated 20-2-1986 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, is hereby published for general information].

Shimla-2, the 20th February, 1986

No. GAD(PA)-4(D)-49/78-C. IV.—In exercise of the powers conferred by section 8-A of the Salaries and Allowances of Deputy Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 5 of 1971),

the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1982, published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra-ordinary) vide Notification No. GAD(PA)-4(D)46/82, dated 22-2-1983, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance of Loan for House Building) (Amendment) Rules, 1986.

(2) These rules shall come into force at once.

2. **Amendment of rule 4.**—For the word “sixty” occurring in rule 4 of the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance of Loan for House Building) Rules, 1982 (hereinafter called the “said rules”) the words “one lakh and twenty” shall be substituted; and for the sign “.” occurring at the end of rule 4 of the said rules, the sign “:” shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that in case a Deputy Minister has taken the motor car advance under rule 4 of the Himachal Pradesh Deputy Ministers (Advance for Motor Car) Rules, 1971, the total amount of the house building advance together with the motor car advance already availed of by a Deputy Minister shall not exceed the limit of one lakh and twenty thousand rupees.”.

शिमला-171002, 20 फरवरी, 1986

संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०)-4 (डी)-49/78-सी-IV.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव असम्बली स्पीकर एण्ड डिप्टी स्पीकर सैलरी ऐक्ट, 1971 (1971 का 4) की धारा 7-ए के साथ पठित धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 17-4-81 में, अधिसूचना संख्या जी० ए० डी० (पी० ए०)-4 (डी) 49/78-सी भाग-II, तारीख 2-4-1981 द्वारा प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के (भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण) नियम, 1981 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष (भवन निर्माण के लिए अग्रिम ऋण) नियम, 1986 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष (भवन निर्माण हेतु अग्रिम ऋण) नियम, 1981 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “कथित नियम” कहा गया है) के नियम 4 में शब्द “साठ” के लिए शब्द “एक लाख और बीस” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और कथित नियमों के नियम 4 के अन्त में चिह्न “.” के लिए चिह्न “:” प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक “क” जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव असम्बली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर (एडवान्स फार मोटर कार) क्लज, 1971 के नियम 4 के अधीन मोटर कार के लिए अग्रिम ऋण लिया हो तो पहले यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा लिये गए मोटर कार के लिए अग्रिम ऋण सहित भवन निर्माण अग्रिम ऋण की कुल राशि एक लाख और बीस हजार रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी।”

[Authoritative English text of the notification No. GAD (PA)-4(D)-49/78-C-IV, dated 20-2-1986 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, is hereby published for general information].

Shimla-2, the 20th February, 1986

No. GAD(PA)-4(D)-49/78-C-IV.—In exercise of the powers conferred by section 13 read with section 7-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries

Act, 1971 (Act No. 4 of 1971), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981, published in the Himachal Pradesh Rajpatra (Extra-ordinary) dated the 17th April, 1981 vide notification No. GAD(PA)-4(D)-49/78-C.VI-II, dated 2-4-1981, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loan for House Building) Amendment Rules, 1986.

(2) These rules shall come into force at once.

2. Amendment of rule 4.—For the word “sixty” occurring in rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance of Loan for House Building) Rules, 1981 (hereinafter called the “said rules”), the words “one lakh and twenty” shall be substituted; and for the sign “.” occurring at the end of rule 4 of the said rules, the sign “:” shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that in case the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, has taken the motor car advance under rule 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's (Advance for Motor Car) Rules, 1971 the total amount of house building advance together with the motor car advance already availed of by the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, shall not exceed the limit of one lakh and twenty thousand rupees.”

R. K. ANAND,
Financial Commissioner and Secretary.

आवकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 6 फरवरी, 1986

संख्या ई0 एक्स0 एन0-एफ0 (10)-8/77-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश असाधारण बिक्री कर अधिनियम, 1968 (1968 का 24) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देते हैं कि उक्त धारा की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित वस्तुओं पर माल की बिक्री की प्रथम अवस्था पर कर तुरन्त उद्गृहीत किया जाएगा, अर्थात्:—

टायर और ट्यूब, मोटर के अतिरिक्त कल पुर्जे/एसैसरीज, स्टैंडर्ड दवाइयाँ, पेन्ट, टवायलट गुड्ज (साबुन, केश तेल, क्रीम तथा कपड़े धोने का साबुन), छत के स्लेट, सैनिटरी गुड्ज, हार्डवेयर गुड्ज, मिट्टी का तेल, गुड्ज, मार्बिस, घड़ियाँ, मोटर का तेल, ल्यूब्रीकैंट्स तथा मोबाइल ग्रायल, चाय, सरसों का तेल, पाम का तेल तथा और ऐसे अन्य खाने पकाने के तेल, अनाज तथा दालें, लोहा तथा इस्पात, जिनकी अवस्था इस प्रकार होगी:—

(क) व्यौहारी की स्थिति में, जो किसी ऐसे माल को हिमाचल प्रदेश से बाहर किसी स्थान से हिमाचल प्रदेश में आयात करता है, बिक्री की अवस्था होगी जब ऐसा व्यौहारी ऐसे माल को पहली बार हिमाचल प्रदेश के भीतर बेचता है।

(ख) ऐसे व्यौहारी की स्थिति में, जो ऐसा माल हिमाचल प्रदेश के भीतर निर्मित करता है, बिक्री की अवस्था होगी, जब ऐसा व्यौहारी, ऐसे माल को पहली बार हिमाचल प्रदेश के भीतर बेचता है।

- (ग) किसी अन्य व्याहारी की स्थिति में जिस ने ऐसे माल को ऐसे व्याहारी से नहीं खरीदा है, जो पूर्व-वर्ती खण्डों में निर्दिष्ट है, बिक्री की अवस्था होगी जब ऐसा व्याहारी ऐसे माल को पहली बार हिमाचल प्रदेश के भीतर बेचता है।

आर० के० आनन्द,
सचिव (आवकारी एवं कराधान)।

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 27th February, 1986

No. 6-25/77-TPT.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 14 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1972 (Act No. 4 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exempt the following vehicles of the Kanchi Kamakoti Peetam Jagadguru Sri Sankaracharya Swamigal Mutt, 1, Salai Street, Kanchee Puram, 631502, Tamil Nadu from the payment of token tax in Himachal Pradesh:—

1. Lorry Fargo ABD-416.
2. Lorry Fargo ADT-7342.
3. Standard Van TDH-6018.
4. Standard Van AAN-7217.
5. Hindustan Trucker-TMK-8900.
6. Hindustan Trucker-TVS-50 (2 Nos.).
7. Hindustan Trucker-TNT-0463.
8. Hindustan Trucker-MFU-612.
9. Cycle Rickshaw—1 No.

By order,
O. P. YADAVA,
Secretary.

TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 26th February, 1986

No. STV (IT)-F (5)-9/85.—In exercise of powers vested in him under section 24 (4) of Apprenticeship Act, 1961 (Central Act), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute and notify the State Apprenticeship Council, for the implementation of the Apprentices Act, 1961, with the following composition for a period of 3 years with immediate effect:—

- | | |
|---|----------|
| 1. Secretary (TE) to the Government of Himachal Pradesh | Chairman |
| 2. Secretary (Industries) to the Government of Himachal Pradesh | Member |
| 3. Secretary (LEP) to the Government of Himachal Pradesh | -do- |
| 4. Director of Industries, Himachal Pradesh, Shimla-2. | -do- |
| 5. Labour Commissioner-cum-Director of Employment, Himachal Pradesh, Shimla-171002. | -do- |
| 6. President, Himachal Pradesh Industries Association (to represent employers in the Pvt. sectors). | -do- |

- | | |
|---|-------------------|
| 7. Managing Director, HPMIDC (to represent employers of public undertakings). | Member |
| 8. Managing Director, H.R.T.C., Himachal Pradesh, Shimla | -do- |
| 9. Director of Education, Himachal Pradesh, Shimla-171001 | -do- |
| 10. One representative of Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (D.G.E.T.), New Delhi. | -do- |
| 11. State Apprentices Adviser-cum-Director of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh, Sundernagar, District Mandi. | Member-Secretary. |

The Governor, Himachal Pradesh is also pleased to constitute and notify the District Level Apprenticeship Committee with the following composition for 3 years for carrying out the purposes of the aforesaid Act with immediate effect:—

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Deputy Commissioner | Chairman |
| 2. General Manager, D.I.C. | Member |
| 3. District Education Officer | -do- |
| 4. District Employment Officer | -do- |
| 5. District Sainik Welfare Officer | -do- |
| 6. Labour Inspector of the District | -do- |
| 7. Regional Manager, HRTC of the District | -do- |
| 8. Principal ITI of the District Hq. or senior most Principal of the District ITIs. | Member-Secretary. |

Note.—The District Employment Officer of the concerned District where ITI is not located will act as Member-Secretary and in case of the District where more than one ITI is located, the senior most Principal of the ITI concerned, will act as Member-Secretary of the District-level Apprenticeship Committee.

The non-official members shall receive TA/DA in respect of the journeys performed by them in connection with the work of the above-mentioned Council/Committee as per detailed rules in this regard stated at annexure-A, as admissible to Himachal Pradesh Government servants of the 1st class.

This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained *vide* their Dy. No. 173-Fin. (C) A (3) 3/82, dated 23-1-1986.

ANNEXURE-A

The non-official/official members of this Committee will be entitled to the travelling allowance and daily allowance as under:—

(1) *Members who are neither State Government Employees nor the Central Government Employees nor Himachal Pradesh University/Autonomous Body Employees:*

1. TRAVELLING ALLOWANCE:

(i) *Journey by Rail.*—He will be treated at par with Government servant of the first grade and will be entitled to actual rail fare of the class of accommodation actually used but not exceeding the fare to which the Government servant of the first grade is normally entitled, *i.e.*, accommodation of the highest class, by whatever name it may be called, provided on the railway by which the journey is performed, except A.C.C. in accordance with the modified T.A. instructions issued *vide* O.M. No. Fin. (C) B (7) 14/78, dated 8th February, 1980 and other orders issued from time to time.

(ii) *Journey by Road*.—He will be entitled to actual fare for travelling by taking a single seat in a public bus and if the journey is performed by motor cycle/scooter, mileage allowance @Rs. 0.50 paise per km. for plain areas and 0.65 paise per km. for hilly areas and if the journey is performed by own car/full taxi the members will be entitled to mileage allowance at Rs. 1.65 paise per km. in respect of the journeys in the plain and Rs. 2.00 paise per km. in the hills subject to the provision of Government instructions issued vide F.D.'s O.M. No. FIN (C)-A(3)-1/80 dated the 25th November, 1980.

(iii) In addition to the actual fare or mileage as per item (i) and (ii) above, a member shall draw daily allowance for the entire absence from his permanent place of residence starting with departure from that place and ending with arrival at that place at the same rate and subject to the same terms and conditions as apply to grade-I officers of the State Government.

2. DAILY ALLOWANCE:

(i) Non-official members will be entitled to draw daily allowance for each day of the meeting at the highest rates as admissible to a Government servant of the first grade for the respective locality.

(ii) In addition to daily allowance for the day(s) of the meeting, a member shall also be entitled to Daily Allowance for the halt or on tour at out station in connection with the affairs of the Committee as under:—

- | | |
|---|----------|
| (a) If the absence from Headquarters does not exceed 6 hours | .. Nil. |
| (b) If the absence from Headquarters exceeds 6 hours but does not exceed 12 hours | .. 70% |
| (c) If the absence from Headquarters exceeds 12 hours | .. Full. |

3. CONVEYANCE ALLOWANCE:

A member resident at a place where the meeting of the Committee is held will not be entitled to travelling and daily allowances on the scales indicated above, but will be allowed only the actual cost of conveyance hire, subject to a maximum of Rs. 10.00 per day. Before the claim is actually paid the controlling officer should verify the claims and satisfy himself after obtaining such details as may be considered necessary that the actual expenditure was not less than the amount claimed.

If such a member used his own car, he will be granted mileage allowance at the rates admissible to officials of the 1st grade subject to maximum of Rs. 10.00 per day.

4. The travelling and daily allowance will be admissible to a member on production of certificate by him to the effect that he has not drawn any travelling or daily allowance for the same journey and halts from any other Government source.

5. The member will be eligible for travelling allowance for the journey actually performed in connection with the meeting of the Committee from and back to the place of their permanent residence to be named in advance. If a member performs journey from a place other than the place of his permanent residence after the termination of the meeting, travelling allowance shall be worked out on the basis of the distance actually travelled or the distance between the place of permanent residence and the venue of the meeting, whichever is less.

6. The provisions of rule 4.17 and 6.1 of the Himachal Pradesh Treasury Rules will apply mutatis mutandis in the case of over payment made on account of travelling allowance to non-official members.

(II) Official Members:

The official members of the Board will be entitled to T.A./D.A. admissible to them according to the rules applicable to them for attending the meetings from the respective Department.

The Director, Technical Education, Vocational and Industrial Training, Himachal Pradesh Sundernagar, District Mandi will be the Controlling Officer in regard to the countersigning of the T.A. bills of the non-official members and T. A. bills of these members will also be prepared in the Directorate of Technical Education, Sundernagar. The expenditure will be debitable to the respective head of the Directorate.

By order,
M. K. KAW,
Commissioner-cum-Secretary.